

प्रभक,
मनीषा पवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
उत्तराखण्ड, देहरादून।
पंचायतीराल अनुभाग-1
विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत प्रथम अनुपूर्वक मांग में प्राविष्टानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।
देहरादून, दिनांक : 12 जनवरी, 2018

उपर्युक्त विषयक विल अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 1362/3(150) XXVII(1)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूर्वक मांग में प्राविष्टानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या: 05 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरणीय तालिका-4 एवं संलग्न अलॉटमेंट आर्डर 05 के अनुसार मानक मद संख्या-01, 03 एवं 06 की कुल धनराशि रु0 1700 हजार (रु0 सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निर्वाचन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूर्वक अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में अन्य शर्तें वही होंगी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृति में निर्गत किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-610 दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित हैं। अतः शासनादेश दिनांक 30.06.2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त व्यय शर्तें वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या: 05 के मुख्य लेखाधीनक 2015-निर्वाचन-109-पंचायती/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार की सुसंगत मानक मदों के नाम ज्ञाना जायेगा। यह आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग एवं उसके अधीन सम्स्त कार्यालयों के लिए कि या जा रहा है।

3. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वाचन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण अधिकांशियों के निर्वाचन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकांशियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी.एम.-8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :- सूची/अलॉटमेंट आर्डर।

भवदीया,
(मनीषा पवार)
प्रमुख सचिव।

